

भारत सरकार  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
औषधि विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 56  
दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्र

56. श्रीमती डिम्पल यादव:  
श्री रमेश बिधूड़ी:  
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:  
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सहित देश में स्थापित जन औषधि केन्द्रों (जेएके) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में जन औषधि केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केन्द्र संचालित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और उक्त प्रयोजनार्थ अनुमानित वित्तीय परिव्यय कितना है;
- (घ) देश भर में प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) देश भर में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के साथ-साथ पीएमबीजेपी का प्रभाव क्या; और
- (च) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत और अधिक दवाओं को शामिल करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पीएमबीजेपी के कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत, देश के 785 जिलों में से 754 जिलों को कवर करते हुए देश भर में 31.12.2023 तक 10454 प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले गए हैं, जिनमें से 07 पीएमबीजेके उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में खोले गए हैं। दिनांक 31.12.2023 तक देश भर में खोले गए पीएमबीजेके की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): सरकार ने देश भर में 31 मार्च, 2026 तक 25000 प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोलने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीआई ने देश के सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रक्रिया से ब्लॉक और जिला स्तर पर जन औषधि केंद्र खोलने में सुविधा होगी।

(घ): योजना के अंतर्गत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है।

(ङ): पिछले 9 वर्षों में, केंद्रों के माध्यम से की गई दवाओं की बिक्री से ब्रांडेड दवाओं की तुलना में नागरिकों को 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीजेपी स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोजगार का अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रहा है और विभिन्न स्तरों पर रोजगार उत्पन्न कर रहा है। इसने देश के 21000 से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को योजना में शामिल करके स्थायी रोजगार का सीधा स्रोत प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त, औसतन 10-12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों (जेएके) में जाते हैं और अपना पैसा बचाकर पर्याप्त लाभ उठाते हैं।

मौजूदा विजन लक्ष्यों के अनुसार, देश में दिनांक 31.03.2024 तक लगभग 10,000 केंद्र खोले जाने हैं। इसके विपरीत, दिनांक 31.12.2023 तक 10454 केंद्र खोले गए हैं।

(च): पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में 1965 दवाएं और 293 सर्जिकल / उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं जिनमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर रोधी, एनिट-डायबिटिक्स, संक्रमण रोधी, एलर्जी, गैस्ट्रो-आंत्र दवाएं आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट-आधारित खाद्य पूरक आदि और कुछ आयुष उत्पाद जैसे आयुरक्षा किट, बालरक्षा किट और आयुष-64 टैबलेट को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में परियोजना की उत्पाद टोकरी में जोड़ा गया है, जिसे चयनित केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना के कामकाज में सुधार करने के लिए, पीएमबीजेपी में मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एप्लिकेशन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सक्षम पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को लागू किया गया है। पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के पास देश भर में जन औषधि केंद्रों में दवाओं और सर्जिकल की आपूर्ति करने के लिए गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में केंद्रीय और क्षेत्रीय माल-गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में 36 राज्य स्तरीय वितरक हैं जो सभी जन औषधि केंद्रों को दवाओं की आपूर्ति करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आम जनता को उनकी उंगलियों पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन "जनऔषधि सुगम" भी शुरू किया गया है, जिसके आधार पर वे कई उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं जैसे - पास का पीएमबीजेके (गूगल मानचित्रों के माध्यम से निर्देशित दिशा) पता लगाएं, जन औषधि दवाएं खोजें, एमआरपी और समग्र बचत आदि के रूप में जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवा की उत्पाद तुलना का विश्लेषण करें।

**अनुलग्नक**

जन औषधि केंद्र के संबंध में श्रीमती डिम्पल यादव, श्री रमेश बिधूडी, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 02.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण

दिनांक 31.12.2023 तक खोले गए पीएमबीजेके की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोले गए पीएमबीजेके की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	9
2	आंध्र प्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	31
4	असम	123
5	बिहार	514
6	चंडीगढ़	11
7	छत्तीसगढ़	220
8	दिल्ली	415
9	गोवा	13
10	गुजरात	624
11	हरियाणा	291
12	हिमाचल प्रदेश	66
13	जम्मू और कश्मीर	255
14	झारखंड	101
15	कर्नाटक	1158
16	केरल	975
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप*	0
19	मध्य प्रदेश	332
20	महाराष्ट्र	587
21	मणिपुर	38
22	मेघालय	18
23	मिजोरम	12

24	नागालैंड	20
25	ओडिशा	488
26	पुदुचेरी	24
27	पंजाब	343
28	राजस्थान	237
29	सिक्किम	6
30	तमिलनाडु	902
31	तेलंगाना	192
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	35
33	त्रिपुरा	25
34	उत्तर प्रदेश	1595
35	उत्तराखंड	228
36	पश्चिम बंगाल	342
<b>कुल</b>		<b>10,454</b>

\*दवाओं की आपूर्ति सीधे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन को की जाती है

\*\*\*\*\*